



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-261985
CG-DL-E-27032025-261985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/ चैत्र 4, 1947

No. 89]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/ CHAITRA 4, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025
मामला सं. – एमटीआर 03/2023

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की
मध्यावधिक समीक्षा

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 07/15/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

1. चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद “संबद्ध देश” के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर (जिसे इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों में पाटन की प्रकृति और सीमा तथा घरेलू उद्योग पर इसके क्षतिकारी प्रभाव की जांच करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) ने दिनांक 28 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. स. 6/38/2020- डीजीटीआर के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 27 दिसंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 77/2021 – सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया।
2. अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/38/2020- डीजीटीआर जारी होने के बाद, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातक, अर्थात् हांगजो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और एक भारतीय आयातक, अर्थात् फकीरसंस पापचेम प्राइवेट लिमिटेड ने अंतिम जांच परिणामों को चुनौती देते हुए वाणिज्य विभाग (प्रतिवादी संख्या 1), राजस्व विभाग (प्रतिवादी संख्या 2) और निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष सिविल आवेदन संख्या 16555/2021 प्रस्तुत किया। रिट आवेदकों ने यह तर्क दिया कि निर्यातक के साथ असहयोगी व्यवहार किया गया, जबकि उसने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी और डेटा प्रस्तुत किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह उक्त निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रख कर इस संबंध में एक सिफारिश जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मई 2022 की अधिसूचना संख्या 15/2022- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रभावी किया गया।
3. निर्दिष्ट प्राधिकारी को हांगजो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फकीरसंस पापचेम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक निर्यातक/ आयातक” के रूप में भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें मार्जिन की मात्रा के पुनः निर्धारण का अनुरोध किया गया था।
4. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारतीय लेमिनेट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (जिसे इसके बाद “आवेदक एसोसिएशन” के रूप में भी कहा गया है) से उसके सदस्यों सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और थान्साऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट करने का अनुरोध करते हुए एक और आवेदन प्राप्त हुआ।
5. और जबकि, आवेदक निर्यातक/ आयातक और आवेदक एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदनों को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च 2023 की अधिसूचना संख्या 7/15/2023- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की व्यापक मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत की गई।

ख. प्रक्रिया

6. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - क. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च 2024 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

- ग. प्राधिकारी ने भारत स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक निर्यातक/ आयातक और आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत में अपने दूतावास के माध्यम से आवेदनों के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, उनके द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उपलब्ध कराई गई।
- ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :
- चांगलकेयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड
 - हांगजो हुआवोन न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड
 - क्यूफेंग न्यू मैटेरियल लिमिटेड बनाम शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड
 - जियान्हे कंपनी लिमिटेड
 - झेजियांग जियान्हे न्यू मैटेरियल सेल्स कंपनी लिमिटेड
 - ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह चीन जन. गण. के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करके उत्तर दिया है :
- चांगलकेयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड
 - हांगजो हुआवोन न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - किंगडेकोर (झेजियांग) कं, लिमिटेड
 - शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड
 - विंबोनटेक्नोसेल न्यू मैटेरियल्स, कं, लिमिटेड
 - जिबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी तथा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की :
- आइका लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स लिमिटेड
 - कलर एक्सपर्ट्स
 - डेको मीका लिमिटेड
 - फकीरसन्स पापचेम प्राइवेट लिमिटेड
 - फैसी रोटो प्रिंट्स
 - ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी
 - मारुति डेकोर
 - मारुति पेपर चेर्न
 - मैच ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - मैचवेल
 - एमबी पेपर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - माइक्रोटेकप्रिंटेज प्राइवेट लिमिटेड
 - पिक्सल प्रिंटर्स
 - प्रिंटिक इंडस्ट्रीज
 - सांवलिया इम्पेक्स एलएलपी

- xix. सराफ सेल्स कॉरपोरेशन
- xx. साया पेपर प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. शिनडेकोर
- xxii. शिवम पेपर प्रिंट
- xxiii. सिल्वर पेपर प्रिंट
- xxiv. स्लिक मीका प्राइवेट लिमिटेड
- xxv. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxvi. सरफेस डेकोर प्राइवेट लिमिटेड
- xxvii. तनिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xxviii. यूनिक डेकोर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- xxix. विनायक डेकोर विजन प्रिंटर्स

- झ. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके प्रतिक्रिया दी है :
- क. थान्सौ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड
- ख. फकीरसन्स पापचेम प्राइवेट लिमिटेड
- ग. सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स लिमिटेड
- घ. सिडमार्क सेल्स सिनर्जी एलएलपी
- ड. मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ञ. क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन -वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम्स महानिदेशालय से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देन की उचित जांच किए जाने के बाद आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स पर भरोसा किया है।
- ट. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।
- ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवंबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें, उसके बाद यदि कोई रिजवाइंडर अनुरोध हो तो प्रस्तुत करें।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच के दौरान किए गए अनुरोधों को, जहां तक ये साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए जाते हैं, प्राधिकारी द्वारा उन पर समुचित रूप से विचार किए गए हैं।
- ढ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- त. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया है अथवा अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/ टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- थ. इस अंतिम जांच परिणाम में '****' हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- द. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यू.एस. डॉलर = ₹ 83.69 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. मूल जांच और वर्तमान जांच के लिए जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है :

"विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, बेट टेसाइल मजबूती 6-12 एन/ 15 एमएम और गुरले पोरोसिटी 10-40 सेकंड/ 100 एमएम है तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रूप होते हैं" (जिसे इसके बाद "डेकोर पेपर" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा कम दाब (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दाब अथवा कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर शामिल नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं, जैसे सरफेसिंग पेपर (सफ़ेद/ऑफ़-व्हाइट), लाइनर (सफ़ेद/ऑफ़-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफ़ेद)। यह वैक्सिंग, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग के लिए बेस पेपर के रूप में आयातित किया जा सकता है और यह विभिन्न आकारों जैसे 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के विभिन्न आकारों में आ सकते हैं।

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48059100 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राधिकारी ने उक्त जांच में सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48022090 के अंतर्गत आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर भी विचार किया है। दोनों सीमा शुल्क वर्गीकरणों पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं :

- i. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, मूल जांच में पीसीएन पद्धति में प्रयुक्त मापदंडों में परिवर्तन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं।
- ii. चूंकि इसका प्रयोजन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन न होने की स्थिति में मुद्रित डेकोर पेपर को उत्पाद के दायरे से बाहर करना था, चाहे वह पेपर उपयोग के लिए तैयार हो अथवा नहीं, यह अप्रासंगिक है।
- iii. चूंकि सभी पेपर, जिनमें मुद्रित पेपर भी शामिल है, को लेमिनेशन पर उपयोग किए जाने के लिए कतिपय इम्प्रेगनेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अतः "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश का उपयोग एक तकनीकी अर्हता बनाता है, जिससे उत्पाद की निकासी के समय समस्याएं पैदा होती हैं।
- iv. "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश के उपयोग के कारण, पाटनरोधी शुल्क को सीमा शुल्क शीर्ष 4811 के तहत आयातित मुद्रित पेपर तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष 4811 मुद्रित पेपर के बीच अंतर नहीं करता है कि वह उपयोग के लिए तैयार है या नहीं, अतः, ऐसी अर्हता शामिल नहीं की जानी चाहिए थी।
- v. हाल ही के एक आदेश में आयुक्त अपील, सीमा शुल्क - कोलकाता ने यह माना है कि सजावटी पेपर एक बार प्रिंट हो जाने के बाद, वह उपयोग के लिए तैयार है, और इस प्रकार, इसके आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है। तथापि, इस पहलू पर कोई नियम नहीं दिया गया है और इसे व्याख्या करने के लिए छोड़ दिया गया है।
- vi. चूंकि धोखाधड़ी के मामले में एक अलग जांच का प्रावधान है, अतः धोखाधड़ी के भय से "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश का उपयोग करके उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. जिस उत्पाद को बाहर करने का अनुरोध किया गया है, वह मुद्रित किया गया उपयोग-के लिए-तैयार पेपर है, जिसे पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर याचिका में केवल बाहर रखे गए उत्पाद के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में परिवर्तन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी परिवर्तन किए जाने से लागू पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन होने की संभावना है।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उत्पाद के दायरे को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उल्लंघन की संभावना को रोका जा सके, जैसा कि हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीईएसटीएटी द्वारा किया गया था।
- iv. मुद्रित उपयोग- के लिए-तैयार पेपर सीमा शुल्क शीर्ष 4811 के अंतर्गत आता है, जिस पर प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की थी और जो किसी भी पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित नहीं करता है।
- v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश से मुद्रित डेकोर पेपर के आयात में बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि उत्पाद स्वयं ही एक अलग सीमा शुल्क शीर्षक के अंतर्गत आता है।
- vi. मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर को पर्याप्त मात्रा में एचएस कोड 4811 के तहत आयात किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि अन्य पक्षकार बिना किसी चुनौती के इसे मंजूरी देने में सक्षम हैं। आवेदक आयातकों के समक्ष समस्या केवल आयात की गलत घोषणा किए जाने के कारण है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश में एचएस कोड 4811 को शामिल किए जाने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क यथाअधिसूचित उत्पाद के दायरे पर लागू होता है, जब उसे यथाअधिसूचित सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत आयात किया जाता है।
- viii. चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया मामला शुल्क आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में है, अतः डीजीटीआर इसे स्पष्ट करने के लिए सही प्राधिकारी नहीं हैं। आयातकों को उनके द्वारा उठाए गए मामलों के समाधान के लिए संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
- ix. यह मामला सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से संबोधित किया गया है, क्योंकि आयुक्त अपील द्वारा पहले ही यह माना जा चुका है कि एचएस कोड 4811 के अंतर्गत आयातित मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- x. आवेदक एसोसिएशन के सदस्य भी मूल जांच में हितबद्ध पक्षकार थे और प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों को उत्पाद के दायरे पर टिप्पणी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। तथापि, आयातकों द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
- xi. पीसीएन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध विरोधाभासी प्रकृति के हैं। निर्यातक ने स्वयं ही यह अनुरोध किया है कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हो गया है, यह वेल्यू चेन में ऊपर चला गया है और उपभोक्ता वरीयता में बदलाव हो गया है। इससे पीसीएन में बदलाव करना आवश्यक हो गया है।
- xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने अथवा विचाराधीन उत्पाद से बाहर करने पर एचएस कोड में परिभाषित नहीं करने पर कोई रोक नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है, जिन्हें डेकोर बेस पेपर, उच्च दाब या कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोर पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में जाना जाता है। मूल पाटनरोधी

जांच के दौरान, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि वह मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर का उत्पादन नहीं करता है और इस प्रकार, ऐसे पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था।

11. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क केवल एचएस कोड 48022090 और 48059100 के अंतर्गत आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाया गया है।
12. आवेदक एसोसिएशन और उसके सदस्यों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। आयातकों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग मुद्रित डेकोर पेपर का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर को पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्पाद के दायरे का विवरण बदलने के अनुरोध और उत्पाद विवरण से "उपयोग- के लिए-तैयार" शब्द हटाने के अनुरोध की नीचे विस्तार से जांच की गई है।
13. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क केवल एचएस कोड 4802 20 90 और 4805 91 00 पर लगाया गया है। मुद्रित डेकोर पेपर उक्त एचएस कोड में नहीं आता है, बल्कि शीर्ष 4811 के अंतर्गत आता है। प्राधिकारी ने उक्त शीर्षक के अंतर्गत आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में भी ऐसे शीर्ष पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।
14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उत्पाद विवरण महत्वपूर्ण है कि व्यापार उपचारी कार्रवाई के प्रयोजन को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, लेकिन इसका ऐसे अन्य उत्पादों पर कोई अनपेक्षित परिणाम न हो, जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए कि यह परिभाषा की व्याख्या के अधीन हो जाए और उन उत्पादों के आयातकों पर अनुचित बोझ पड़े, जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि घरेलू उद्योग मुद्रित डेकोर पेपर के आयातों से व्यथित नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह विचाराधीन उत्पाद के समान अथवा अदला-बदली करने योग्य उत्पाद है। घरेलू उद्योग ने इस बात का कोई औचित्य नहीं दिया है कि "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश क्यों आवश्यक है। वाक्यांश की व्याख्या व्यक्तिपरक तरीके से की जा सकती है और उसमें बहिष्करण की उपयुक्तता से कोई मूल्यवर्धन नहीं होता है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण एक महत्वपूर्ण आधार है जिस पर पाटनरोधी कार्यवाही शुरू की जाती है और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है।
15. अतः इच्छिटी के हित में, प्राधिकारी यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि शीर्ष 4811 के तहत मुद्रित डेकोर पेपर के आयातों को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अतः प्राधिकारी "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटाते हैं। निम्नलिखित परिभाषा लागू होगी।

"विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, वेट टेन्साइल मजबूती 6-12 एन/ 15 एमएम और गुरले पोरोसिटी 10-40 सेकंड/ 100 एमएल है तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रूप होते हैं" (जिसे इसके बाद "डेकोर पेपर" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा कम दाब (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दाब अथवा कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें 4811 शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है।"

16. पीसीएन में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार से दी गई समय सीमा के भीतर टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः मूल जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति पर वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के लिए विचार किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में आवेदकों अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :
- भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन उत्पादक हैं, अर्थात् आईटीसी लिमिटेड, पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स और श्री कृष्णा पेपर्स।
 - आईटीसी लिमिटेड के पास भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और यह घरेलू उद्योग में शामिल है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग इस प्रकार है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।”

20. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आईटीसी लिमिटेड के पास भारत में घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और इसका भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, आईटीसी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इस प्रकार, आईटीसी लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग में आता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विभिन्न उल्लंघन किए गए हैं।
- निर्यातकों/ उत्पादकों ने औचित्य प्रदान किए बिना उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों के नामों को गोपनीय बताया है। किंगडेकोर ने तो अपने ब्रॉशर को भी गोपनीय बताया है।
- विनबॉन ने भारत को निर्यात किए गए उत्पाद प्रकार (पीसीएन), उत्पादन सुविधाओं, संबद्धताओं और शेयरधारक सूचनाओं को प्रकट नहीं किया है।
- हुआवांग और सिडमार्क ने वितरण के चैनल को पूरी तरह से गोपनीय बताया है।

- v. उत्पादकों/ निर्यातकों ने परिशिष्ट-1 को पूरी तरह से गोपनीय बताया है।
- vi. विनबॉन, हुआवांग और चांगल उचित तुलना के लिए समायोजन के रूप में दावा किए गए व्ययों की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति प्रदान करने में विफल रहे हैं।
- vii. किंगडेकोर, चांगल, शेडोंग और जिबो ने कंपनी संबद्धताओं और शेयरधारकों के बारे में सभी सूचनाओं को गोपनीय बताया है।
- viii. चांगले, शेडोंग और जीबो ने उत्पादन प्रक्रिया को गोपनीय बताया है।
- ix. किंगडेकोर ने प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची को गोपनीय बताया है।
- x. किंगडेकोर ने उत्तर में दी गई समग्र सूचना को गोपनीय बताया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति को भी समझने में असमर्थ है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षाकारों को उपलब्ध कराया।

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 14 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को जहां भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

च. वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा का दायरा

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मध्यावधि समीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. व्यापक समीक्षा की शुरुआत उचित है क्योंकि (क) मार्जिन के पुनः निर्धारण के लिए उल्लिखित किए गए मामले सभी उत्पादकों पर लागू होते हैं, (ख) शुल्क काफी समय से लागू है और (ग) घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम गुलशन लाल मामले में दिया गया निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि शुल्क को निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा

- करना प्राधिकारी का दायित्व है। घरेलू उद्योग के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि प्राधिकारी के पास संशोधित शुल्क को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से मूल कच्ची सामग्री और उत्पादन के अन्य कारकों की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इससे उत्पाद मिश्रण में बदलाव आया है।
 - iii. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्क किसी भी समय पाटन और क्षति के मार्जिन से अधिक न हो। स्थायी प्रकृति के परिवर्तनों की आवश्यकता केवल शुल्क के निरसन के मामलों में लागू होती है, न कि शुल्क की मात्रा के पुनः निर्धारण के लिए लागू होती है।
 - iv. लुगदी की लागत में 20-30% तक की वृद्धि हुई है और अन्य प्रमुख इनपुट जैसे टाइटेनियम, काओलिन, ऊर्जा और श्रम की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में करीब 15-30% तक की वृद्धि हुई है।
 - v. आईटीसी सहित वैश्विक बाजार में बुनियादी कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट की लागत और कीमत में काफी वृद्धि हुई है। ये प्रवृत्ति स्थायी प्रकृति की है और इसके जारी रहने की संभावना है।
 - vi. उच्च कीमत और गुणवत्ता वाले उत्पादों के संबंध में आयातों में बदलाव आया है, जो उपभोक्ता वरीयता में बदलाव को दर्शाता है, जो एक स्थायी प्रकृति का है।
 - vii. प्राधिकारी को पूर्ण मध्यावधि समीक्षा आरंभ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आवेदकों और घरेलू उद्योग ने चीन से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध नहीं किया है।
 - viii. नियम 23 के अनुसार, पाटनरोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकारी आवेदकों के दावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। चूंकि किसी भी आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया है, अतः लागू शुल्कों को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।
 - ix. वर्तमान जांच में शुल्क को या तो बनाए रखा जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध भी नहीं किया है।
 - x. चांगल ने जांच की मूल अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और वर्तमान जांच में दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर उसे व्यक्तिगत शुल्क दिया जाना चाहिए।
 - xi. किंगडेकोर ने वर्तमान जांच में पूर्ण उत्तर दाखिल किया है और उसे प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन दिया जाना चाहिए।
 - xii. विंबोनेट्रोसेल एक नया उत्पादक है और भारत सहित सभी देशों को केवल उच्च-स्तर के उत्पादों का निर्यात अपाटित कीमतों पर करता है।
 - xiii. उत्पाद मिश्रण और संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों में परिवर्तन के कारण, हांगजो हुआबांग पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पुनः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:-

- i. चूंकि वर्तमान जांच का दायरा, दायर किए गए आवेदन और आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत से बहुत बड़ा है, वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ii. चूंकि वर्तमान समीक्षा स्वतः प्रेरणा समीक्षा नहीं है और निर्यातकों और आयातकों द्वारा दायर आवेदन के आधार पर आरंभ की गई है, वर्तमान जांच के दायरे को मांगी गई राहत तक सीमित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच में स्वतः प्रेरणा समीक्षा का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई आधार अथवा कारक नहीं हैं।
- iii. आवेदकों द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था जो व्यापक समीक्षा की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध कर सके।
- iv. निर्यातक ने यह स्थापित नहीं किया है कि बताए गए परिवर्तन किसी समीक्षा का औचित्यसिद्ध कर सकते हैं, विशेषकर क्योंकि पाटन मार्जिन पहचाने गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित नहीं हुआ है।
- v. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के विपरीत, यह बताने के लिए कोई साक्ष्य अथवा न्यायशास्त्र नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समय के किसी भी बिंदु पर पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यूएसए के अलावा, किसी भी जांचकर्ता प्राधिकारी ने, यह

- सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क की पुनरावृत्ति समीक्षा आयोजित नहीं की है कि मात्रा वर्तमान पाटन से अधिक नहीं है।
- vi. मार्जिन के पुनर्परिमाणीकरण के लिए निर्यातकों द्वारा पहचाने गए कारकों को स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं माना जा सकता है जिससे शुल्क का पुनः परिमाणीकरण आवश्यक हो जाता है।
 - vii. कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव एक नियमित व्यावसाय परिदृश्य है, क्योंकि पल्प की कीमतों में वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव होने की प्रवृत्ति है। वास्तव में, पल्प की कीमतों में जांच की अवधि के पश्चात गिरावट आई है। ऐसे परिवर्तन को स्थायी प्रकृति का नहीं माना जा सकता है।
 - viii. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क के पुनः प्रमाणीकरण की मांग करने वाले उच्च कीमत वाले उत्पाद के प्रति भारत में उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन आया है।
 - ix. उत्पाद मिश्र में परिवर्तन और ऊंची कीमत वाले उत्पाद के निर्यातों में वृद्धि शुल्क के मिश्रित रूप का परिणाम है जो कम कीमत वाले उत्पादकों को अलाभकारी बनाते हैं। इसे शुल्क के पुनः प्रमाणीकरण के लिए आधार नहीं माना जा सकता।
 - x. संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमत शुल्क के पुनः प्रमाणीकरण के लिए आधार नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी कीमत गैर-क्षति रहित कीमत, पहुंच कीमत, निर्मित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में वृद्धि को सूचित करती है और परिणाम स्वरूप शुल्क की मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - xi. उत्पाद मिश्र में परिवर्तन और लागत में और संबद्ध वस्तुओं की लागत में परिवर्तन के लिए एक मध्यवर्ती समीक्षा आयोजित करने से समीक्षाओं का कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाएगा।
 - xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, नियम-23 प्राधिकारी को शुल्कों के पुनः परिमाणन की अनुमति देता है। प्राधिकारी ने पिछली जांचों में पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि की है तब भी जबकि शुल्कों को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था।
 - xiii. निम्न पाटन मार्जिन को प्राप्त करने के लिए आवेदक निर्यातक द्वारा कीमतों में हेरफेर करने की संभावना है। ऐसे निर्यातक द्वारा निर्यातों की मात्रा भारत में मांग की तुलना में काफी कम है और भारत में एकमात्र बिक्री एजेंट को बिक्रिया की गई है। इस बात की संभावना है कि निर्यातक और आयातक द्वारा अल्पावधि के लिए उत्पाद की कीमतों को अधिक रखने के लिए मिली-भगत की गई है।
 - xiv. आवेदक निर्यातक ने आवेदक निर्यातक की कीमतों से काफी कम कीमत पर अन्य आयातकों को कम मात्रा में बिक्री की है। इस कारण आवेदक उत्पादक और आवेदक आयातक के बीच वास्तविक लेन-देन पर संदेह उत्पन्न होता है।
 - xv. यदि प्राधिकारी एक व्यापक समीक्षा जारी रखते हैं, तो शुल्कों को और पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जानी चाहिए। यह प्रचालन पद्धतियों की आचार संहिता के अनुरूप है।
 - xvi. अन्य उत्पादकों से आयातों की मात्रा की तुलना में चांगल से आयातों की मात्रा को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है तो यह निम्नतर मार्जिन प्राप्त करने के लिए कीमतों में हेरफेर की गुंजाइश छोड़ता है।
 - xvii. नई शिपर समीक्षा की जरूरतों को वर्तमान जांच में उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात, जिन्होंने जांच की मूल अवधि में निर्यात नहीं किए थे, पृथक मार्जिन प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक मात्राओं में होने चाहिए।
 - xviii. पृथक पाटनरोधी शुल्क प्रदान करने के लिए निर्यातक का उत्पाद प्रोफाइल और विभिन्न उत्पाद प्रकारों के निर्यातों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए।
 - xix. किंगडेकोर के संबंधित पक्षकार, जो कि विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक हैं, ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
 - xx. जहां किंगडेकोर ने दावा किया है कि संबंधित पक्षकार ने भ्रामक घोषणा प्रस्तुत की है क्योंकि इसकी संबंधित पक्षकार पार्टी ने जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। ऐसे माल को किंगडेकोर के लिए प्रयोज्य पाटनरोधी शुल्क के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसी वस्तु का उनके द्वारा विनिर्माण नहीं किया गया था।
 - xxi. जबकि किंगडेकोर ने यह दावा किया है कि संबंधित पक्षकार झियांगे संबद्ध वस्तु का विनिर्माता नहीं है, न ही सीमा शुल्क आयुक्त के निर्णय से यह साक्ष्य है कि झियांगे विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है।

- xxii. किंगडेकोर को दिए गए पृथक शुल्क वापस लिए जाने चाहिए क्योंकि इसने मूल पाटनरोधी जांच में आवश्यक सूचना को छिपाया है और भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई है।
- xxiii. विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमतों में परिवर्तन पाटन मार्जिन में परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह निर्यात कीमत, निर्मित सामान्य मूल्य, पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत को प्रभावित करता है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यवर्ती समीक्षा का दायरा मूल जांच और निर्यातक समीक्षा से भिन्न है। एक मध्यवर्ती समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क के लगातार जारी रहने की आवश्यकता को, जहां जरूरत हो, वहां स्वयं की पहल पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जांच और निर्धारित किए जाने की जरूरत है, जिसने निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के बाद से समय की उचित अवधि के समाप्त होने के पश्चात, ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए नकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है, यदि प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उसमें विभिन्नता पाई जाती है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अब कोई आवश्यकता नहीं है तो ये केन्द्रीय सरकार को इसे वापिस लेने की सिफारिश करेंगे।
29. प्राधिकारी ने पहले चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4 डायमिनॉ स्टीलसीन 2,2 डायसल्फोरिक एसिड (डीएएसडीए) में एक मध्यवर्ती समीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नानुसार नोट किया है:
- “निर्णायक समीक्षा और मध्यवर्ती समीक्षा के संबंध में नियमावली की भाषा को जानबूझकर भिन्न रखा गया है ताकि शुल्क को समाप्त किए जाने की जरूरत को स्थापित करने की सावधानी पर अधिक जोर दिया जा सके। एडी नियमावली के नियम 23(क) में नहीं” शब्द पर जोर संभवतः पाटनरोधी शुल्क को समय से पूर्व समाप्त किए जाने की जांच करते समय एक उच्चतर और कठोर बाध्यता को सूचित करता है।”*
30. प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान पुनरीक्षा आवेदक निर्यातक/आयातक द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन के आरोप पर आधारित है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पाद मिश्र में परिवर्तन किया गया है और संबद्ध वस्तु की कीमत में परिवर्तन है जो शुल्कों के पुनर्माणीकरण का औचित्य सिद्ध करता है। आवेदक निर्यातक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि चिन्हित किए गए पैरामीटर असाधारण हैं और केवल उक्त निर्यातक के लिए प्रयोज्य हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि पहचाने गए पैरामीटर्स संबद्ध देश में सभी निर्यातकों के लिए प्रयोज्य हैं और केवल आवेदक निर्यातक के लिए ही सीमित नहीं हैं, प्राधिकारी ने एक व्यापक समीक्षा आरंभ की थी।
31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत के समय, आवेदक निर्यातक/आयातक ने आधारभूत कच्चे माल अर्थात् पल्प की कीमत तथा साथ ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड तथा काओलिन सहित दूसरे अन्य इनपुटों की कीमत में वृद्धि के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक निर्यातक/आयातक ने अनुरोध किया है कि कच्चे माल और इनपुट की लागत में वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास इसका स्वयं का पल्प है और इस प्रकार आवेदक की उत्पादन की लागत में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता के कारण इसमें वृद्धि नहीं हुई। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत की। इसके अलावा, विवाद की प्रकृति के आधार पर प्राधिकारी ने एक व्यापक समीक्षा की शुरुआत करना उचित समझा।
32. प्राधिकारी ने वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा में किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपना वित्तीय और लागत संबंधी डेटा प्रस्तुत किया है जिसे नीचे दी गई सारणी के अनुसार दर्शाया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत के समय किया गया यह अनुरोध कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग पर लागू नहीं होती, तथ्यात्मक रूप से गलत है:-

क्र.सं.	कच्चा माल	कीमत		अंतर	
		मूल जांच	वर्तमान जांच		
		₹/एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	%
1	पल्प-आयात	***	***	***	***
2	पल्प कैप्टिव	***	***	***	***
3	रसायन	***	***	***	***
4	ब्रोक	***	***	(***)	(***)
5	कुल आरएम लागत			***	22%

33. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की कुल लागत में भी जांच की मूल अवधि की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि में वृद्धि हुई है। अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा है।
34. इन अनुरोधों के संबंध में कि भारत को निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारांशित औसत पहुंच कीमत में हुई वृद्धि घरेलू उद्योग के कच्चे माल की भारांशित औसत कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। जहां कच्चे माल की भारांशित औसत लागत में 23% वृद्धि हुई है वहीं चीन से हुए भारांशित औसत पहुंच कीमत में 22% की वृद्धि हुई है।

पीसीएन कोड	डीजी सिस्टम के अनुसार मात्रा	कच्चे माल की कीमत			
		मूल जांच	वर्तमान जांच	इनमें अंतर	इनमें अंतर
		₹/एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	%
1सी1	53	***	***	***	***
1सी2	52	***	***	***	***
1यू2	0	***	***	***	***
2 सी 1	699	***	***	***	***
2सी2	12,341	***	***	***	***
2यू1	14,328	***	***	***	***
2यू2	10,128	***	***	***	***
3सी1	4,050	***	***	***	***
3सी2	400	***	***	***	***
3यू1	11,462	***	***	***	***
3यू2	2,799	***	***	***	***
अंतर*				***	23%

*भारांशित औसत

विवरण	यूओएम	मूल्य
भारांशित औसत पहुंच कीमत	₹/एमटी	128,817
वर्तमान पीओआई में भारांशित पहुंच कीमत	₹/एमटी	158,055
आवेदक निर्यातक के लिए पहुंच कीमत में वृद्धि	₹/एमटी	***
आयातों की भारांशित औसत पहुंच कीमत में वृद्धि	₹/एमटी	29,238
लैंडेड मूल्य में भारित औसत वृद्धि	%	22.69

35. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक निर्यातक की पहुंच कीमत में हुई वृद्धि चीन जन.गण. की पहुंच कीमत में हुई वृद्धि से भी कम है।

पीसीएन कोड	हांगझोउ हुआवांग न्यू मेटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड				
	मूल जांच		वर्तमान जांच		वर्तमान और मूल में अंतर
	मात्रा	पहुंच कीमत	मात्रा	पहुंच कीमत	
	एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी
1सी1	***	***	***	***	***
1सी2	***	***	***	***	***
1यू2	***	***	***	***	***
2सी1	***	***	***	***	***
2सी2	***	***	***	***	***
2यू1	***	***	***	***	***
2यू2	***	***	***	***	***
3सी1	***	***	***	***	***
3सी2	***	***	***	***	***
3यू1	***	***	***	***	***
3यू2	***	***	***	***	***
कुल (भारांशित औसत)	***	***	***	***	***

36. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जहां आवेदक निर्यातक ने इस तथ्यपर विश्वास किया है कि घरेलू उद्योग के पास कैप्टिव पल्प खपत है जिस कारण इसने उत्पादन की लागत में वृद्धि का सामना नहीं किया है। सूचना के सत्यापन के पश्चात्, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने कैप्टिव रूप से उत्पादित पल्प का केवल 10-20% प्रयोग किया है और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए 80-90% पल्प का आयात किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग पल्प की कीमत में वृद्धि के कारण भी प्रभावित हुआ है।
37. अतः, प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि भारत में निर्यात कीमतों में जिस आधार पर वृद्धि हुई है, वह पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुननिर्धारण की जरूरत को निर्धारित नहीं करता। यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदकों या अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कारक की पहचान नहीं की है जिसने एकतरफा रूप से सामान्य मूल्य को प्रभावित किए बिना केवल निर्यात कीमत में परिवर्तन किया है। इसलिए, इससे यह स्थापित नहीं किया होता कि मूल जांच की पीओआई की तुलना में परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा, यह स्थापित नहीं किया गया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी स्वरूप के हैं। इसलिए, आवेदक निर्यातक के लिए मार्जिन को पुनः निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है।
38. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सिर्फ विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में परिवर्तन को उपायों के संशोधन की मांग करते हुए परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जा सकता। लागत और कीमत में बाजार स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परिवर्तन स्थायी प्रकृति के हैं, इसलिए उपायों में संशोधन की आवश्यकता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, पल्प की कीमतों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, किन्तु उसके बाद पीओआई के पश्चात् उसमें गिरावट आई है। इसलिए, उत्पाद का स्वरूप इस प्रकार का है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है।
39. प्राधिकारी ने, यहां ऊपर किए गए विश्लेषण के आधार पर पाया है कि मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत के लिए यह आधार कि घरेलू उद्योग की लागत में अनुरूपी वृद्धि के बिना उत्पादन की लागत और निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है, को स्थापित नहीं किया गया है।

40. आवेदक निर्यातक/निर्यातक ने भी आरोप लगाया है कि उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन हुआ है जिसमें मार्जिन के पुनर्निर्धारण की जरूरत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने पीसीएन का निर्माण किया है। प्राधिकारी ने मूल जांच में बेचे गए पीसीएन का विश्लेषण किया है और वर्तमान जांच से इसकी तुलना की गई है। यह नोट किया गया है कि मूल जांच में आयातित किए गए पीसीएन का वर्तमान जांच में भी आयात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीसीएन जो मात्रा में उल्लेखनीय थे, वर्तमान अवधि में भी महत्वपूर्ण मात्रा में बने रहेंगे। इस प्रकार, निर्यात के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तथा उपायों के संशोधन के पुनःनिर्धारण के औचित्यको सिद्ध करता है। जांच यह दर्शाती है कि आवेदन में दिया गया यह आधार कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हुआ है, जिसकी पहचान उस समय की गई थी, आरंभ नहीं किया गया है।

पीसीएन कोड	आयात मात्रा	
	मूल जांच के अनुसार	वर्तमान जांच के अनुसार
	एमटी	एमटी
1सी1	-	53
1सी2	326	52
1यू2	-	-
2सी1	1,107	699
2सी2	10,091	12,341
2यू1	4,278	14,328
2यू2	2,378	10,128
3सी1	2,634	4,050
3सी2	372	400
3यू1	2,902	11,462
3यू2	401	2,799

41. प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि आवेदक को इस सीमा तक परिस्थितियों में परिवर्तन स्थापित किए जाने की जरूरत है कि आधार जिस पर शुल्क को लागू किया गया था, में उल्लेखनीय रूप से इतना परिवर्तन हो गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है यदि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उनमें विभिन्नता लाई जाती है। वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच की अवधि के दौरान स्थापित किए गए तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में पहचाने गए आधार विद्यमान नहीं हैं। जांच यह दर्शाती है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं स्थापित किया कि घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है, यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उसमें भिन्नता लाई जाती है। यह स्थापित नहीं किया गया है कि एडीडी की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
42. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि किंगडेकोर जियानहे कं. लिमिटेड एवं संबंधित हस्ती द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की लगातार आपूर्ति करता रहा है, जबकि जियानहे को सिर्फ एक व्यापारी के रूप में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया। किंगडेकोर ने संबंधित वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए इन वस्तुओं को अपने उत्पाद के रूप में घोषित किया। यह अवलोकन किया गया है कि किंगडेकोर ने एक कारखाने सं. 158, टोंगजियांग रोड, शेजिया डेवलपमेंट जोन, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग 32422, चीन में उत्पादित माल का भी निर्यात किया है। तथापि, इसे मूल जांच और साथ ही एमटीआर जांच, दोनों में, किंगडेकोर द्वारा विनिर्माण/उत्पादन इकाई के रूप में कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया।
43. उन दोनों संयंत्रों की जांच किए जाने पर, निर्यातक ने अनुरोध किया है कि इसकी पहली उत्पादन श्रृंखला की श्रृंखला सं. 13 की वर्ष 2006 में सं. 158, टोंगजियांग रोड, शेजिया इकोनोमिक डेवलपमेंट जोन, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग प्रोविंस के रूप में पहचान की गई थी। वर्ष अक्तूबर, 2011 में कंपनी ने अपने परिचालनों को वर्तमान अधिकारिक/पंजीकृत पते सं. 20, साउथ तियानहू रोड, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग प्रोविंस पर विस्तारित किया है।

किंगडेकोरने यह भी कहा है कि इसके व्यापार लाइसेंस में केवल एक अधिकारिक/पंजीकृत पता शामिल है – संख्या 20, साउथ तियानहू रोड। इस आधार पर, किंगडेकोर ने यह दावा किया है कि इसने ईक्यूआर को दायर करते समय केवल अधिकारिक पते को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा, निर्यातक ने स्वीकार किया है कि पीओआई के दौरान इसने दोनों संयंत्रों से उत्पादित पीयूसी का निर्यात किया है।

44. तथापि, निर्यातक प्रश्नावली उत्तर की अनिवार्यताओं से यह साक्ष्य है कि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त है और तथ्यों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने के समान है। ईक्यूआर के सामान्य भाग के बिन्दु 3 और 4 को संदर्भ के लिए नीचे दोबारा प्रस्तुत किया गया है:-

“3. आपके मुख्य कारपोरेट ऑफिस और भारत में आपके कार्यालय आदि कोई हो, का पूर्ण पता दें। उनके टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पता उपलब्ध कराएं। प्रधान संपर्क व्यक्ति (अथवा पाटनरोधी कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ भारत में अथवा वही अन्य स्थान पर प्रतिनिधि/कानूनी प्रतिनिधि) का नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पता बताएं।

4. पूरे पते, टेलीफोन और फैक्स नंबर और ई-मेल पते के साथ जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल कारखानों की सूची।”

45. ये अनिवार्यताएं स्पष्ट रूप से इसे जरूरी बनाती हैं कि निर्यातकों न केवल कारपोरेट आफिस के पते को प्रकट करना होगा बल्कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल सभी कारखानों का पूरा विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि प्राधिकारी को जांचाधीन कंपनी द्वारा माल के उत्पादन और बिक्री संबंधी पूरी जानकारी को जानने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, ईक्यूआर के परिशिष्ट 7 में पीयूसी का उत्पादन करने वाले प्रत्येकसंयंत्र/यूनिट के लिए पृथक रूप से रिपोर्ट किए जाने वाली व्यय और लागत संबंधी सूचना को दिया जाना अपेक्षित है। यह मुद्दा किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में गंभीर शंका उठाता है।
46. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किंगडेकोर अपने उत्पादों की मार्केटिंग में शामिल एक भारतीय हस्ती शाह इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ अपने व्यापार संबंधी रिश्तों को प्रकट करने में असफल रहा है। प्रश्न किए जाने पर, किंग डेकोर ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए व्यापार संबंधों को स्वीकार किया है:

“जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, किंग डेकोर का भारतीय बाजार में केवल एक असंबंधित इंडेंटिंग एजेंट अर्थात् शाह इंटरनेशनल सर्विसेज है। भारतीय क्रयकर्ताओं की जरूरत के अनुसार, शाह किंगडेकोर को आदेश जारी करता है और भारतीय क्रयकर्ताओं को किंगडेकोर द्वारा माल की आपूर्ति के बाद, यह माल के बिक्री मूल्य पर @2% की दर से कमीशन प्राप्त करता है।

कंपनी द्वारा वर्तमान एमटीआर जांच में तथा साथ ही मूल जांच के पीओआई के दौरान अदा की गई छूट (यदि कोई हो) सहित कमीशन को विधिवत समग्र रूप में पीयूसी तथा गैर-पीयूसी, जहां प्रयोज्य हो, कंपनी के लिए “बिक्रियों पर कमीशन” शीर्षक के रूप में शीर्ष “प्रत्यक्ष बिक्री व्ययों” के तहत किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर के परिशिष्ट 7 में रिपोर्ट किया गया है, चूंकि परिशिष्ट 3क सहित किसी अन्य परिशिष्ट में इसे दायर करने से संबंधित कोई निदेश नहीं विद्यमान है।”

47. इसके अतिरिक्त, किंगडेकोर द्वारा उपलब्ध कराए गए करार की प्रति के अनुसार, भारत में वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में परवर्ती को नियोजित करते हुए शाह इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ एक लिखित करार (दिनांक 1 जनवरी, 2019) किया गया है। करार 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है और एक अनिश्चित अवधि के लिए बातचीत की गई। तथापि, किंगडेकोर इस महत्वपूर्ण व्यापार संबंध की रिपोर्ट करने और कारखानागत निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए भुगतान किए गए कमीशन के समायोजन की रिपोर्ट करने में विफल रहा जो महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने का मामला है।

48. 11 अक्तूबर, 2024 को, प्राधिकारी ने उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 की अंतिम समय सीमा को निर्धारित करने के लिए, संबंधित निर्यातकों को दो पूरक प्रश्नावलियां भी जारी की। किंगडेकोर ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2024 तक अर्थात् सात (7) दिनों के विस्तार की मांग करते हुए एक अनुरोध प्रस्तुत किया।

तथापि, उक्त प्रश्नावली के संबंध में आज की तारीख तक किंगडेकोर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है। पूरक प्रश्नावली में पाटन मार्जिन और क्षति माजिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सूचना अन्तर्निहित है।

49. किंगडेकोर प्रस्तुत की गई सूचना की यथार्थता को प्रमाणित करने के लिए अपनी सूचनाओं को सत्यापित कराने में भी असफल रहा है। प्राधिकारी ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 की ईमेल के अनुसार किंगडेकोर को 25 अक्टूबर, 2024 तक अपेक्षित सत्यापन संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि वह वाणिज्यिक इनवॉयस और अन्यप्रासंगिक समर्थक दस्तावेजों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण प्रदान करें। यह अवलोकन किया गया है कि किंगडेकोर इन अनुदेशों का अनुसरण करने में असफल रहा है क्योंकि वाणिज्यिक इनवॉयस और संलग्न दस्तावेजों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए उसकी ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।
50. इसके अतिरिक्त, किंगडेकोर ने इसके निर्यातक के प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) के साथ मूल से प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट 3क के संशोधित पाठ को प्रस्तुत करते हुए सत्यापन दस्तावेजों सहित "परिशिष्ट-किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड परिशिष्ट 3क-सुधार" शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तथापि, ऐसे संशोधन केलिए कारणों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण या औचित्यको न तो कवरिंग ई-मेल और न ही संशोधित परिशिष्ट 3क में अन्तर्निहित किया गया है। यह देखा गया है कि भारत को निर्यात कीमत में समायोजनों से संबंधित संशोधनों को संशोधित दस्तावेज में शामिल किया गया है जो किसी सूचना, स्पष्टीकरण अथवा औचित्य के बिना प्रश्नावली उत्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण है। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रभारों, जिनका मूल ईक्यूआर में प्रकटीकरण नहीं किया गया था, को प्रमाणित करने के लिए किसी स्पष्टीकरण टिप्पणी अथवा पुष्टिकारी साक्ष्य के बिना संशोधित अनुरोध में अब रिपोर्ट किए गए हैं। ये विसंगतियां किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की संपूर्णता, शुद्धता और विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न करती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्वयं ही प्रश्नावली उत्तर को संशोधित किया है, वह भी बिना किसी सूचना के स्पष्टीकरण अथवा औचित्य के, इस प्रकार मूल प्रश्नावली निरर्थक हो गई है। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए औचित्य की अनुपस्थिति और सुस्पष्ट अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ने चल रही जांच के संदर्भ में प्रस्तुत की गई सूचना की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।"
51. जारी जांच को ध्यान में रखते हुए, यह साक्ष्य है कि किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड ने वर्तमान जांच के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने मूल जांच में महत्वपूर्ण जांच को भी छुपाया है, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने किंगडेकोर को पृथक शुल्क प्रदान किए हैं। साथ ही वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना, अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता, असंगत प्रकटीकरण और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (पाटनरोधी नियमावली) के नियम 6(8) के तहत असहयोग को स्थापित करने वाले विशिष्ट अनुदेशों के गैर-अनुपालन। प्राधिकारी ने किंगडेकोर और उत्पादक से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में परिवर्तन किया है और उत्पादक को शेष शुल्कों के अधीन होना पड़ेगा।
52. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यह मामला किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड को छोड़कर, चीन से आवेदक निर्यातक अथवा किसी अन्य उत्पादक के लिए पृथक मार्जिन के पुनः परिमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ज. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. प्रकट विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. लागत संरचनाओं, उत्पाद मिश्रण और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के कारण, पाटनरोधी शुल्क का पुनः मात्राकरण आवश्यक है।
 - ii. कच्चे माल और इनपुट की लागत में काफी बदलाव आया है और इसने निर्यातक की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है।
 - iii. प्राधिकारी का यह अवलोकन कि परिस्थितियों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, अनुचित है।
 - iv. क्षति और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
 - v. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले टिप्पणियों को शामिल करने के लिए एक संशोधित प्रकटन विवरण जारी किया जाए।
 - vi. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की एक स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए और "मुद्रित तैयार-से-उपयोग सजावटी कागज को छोड़कर" शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए।

- vii. उत्पाद वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण आयात के समय भ्रम और प्रशासनिक कठिनाइयाँ हुई हैं।
- viii. घरेलू उद्योग की धोखाधड़ी के बारे में चिंताएँ निराधार हैं, क्योंकि धोखाधड़ी के मुद्दों को नियम 25 के तहत एक अलग जाँच के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है।
- ix. विंबोन एक नया उत्पादक/निर्यातक है जो मूल जांच का हिस्सा नहीं था और उसे अपने स्वयं के आंकड़ों के आधार पर एक अलग पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- x. किंगडेकोर के गलत बयानों ने क्षति विश्लेषण को विकृत कर दिया है और जांच की निष्पक्षता को प्रभावित किया है।
- xi. पाटन मार्जिन गणनाओं को उच्च-मूल्य वाले उत्पाद की बिक्री अलग से मानना चाहिए।
- xii. घरेलू उद्योग और अन्य निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कुछ अनुरोध अत्यधिक संपादित किए गए हैं।
- xiii. किंगडेकोर प्राधिकारी के इस निष्कर्ष का विरोध करते हैं कि वह असहयोगी था।
- xiv. इसने सभी संगत सूचना समय पर प्रस्तुत की और संकेत दिए जाने पर अपने उत्तरों को स्पष्ट किया।
- xv. किंगडेकोर ने दोहराया कि नंबर 158 एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि उसी कंपनी के तहत एक कार्यशाला है और सभी लेखांकन, बीजक और पंजीकरण नंबर 20 तियानहु साउथ रोड से केंद्रीय रूप से संचालित किए जाते हैं।
- xvi. किंगडेकोर का तर्क है कि नंबर 158 का प्रकटन अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह एक अलग कानूनी इकाई नहीं थी।
- xvii. शाह इंटरनेशनल सर्विसेज, भारत में संचालित एक गैर-संबंधित इंडेंट एजेंट है और भुगतान किए गए सभी कमीशन का प्रकटन परिशिष्ट-7 में प्रत्यक्ष बिक्री व्यय के तहत किया गया था।
- xviii. किंगडेकोर ने स्पष्ट किया कि केडी और एक्सएच दोनों श्रृंखलाएं इसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं और एक्सएच श्रृंखला का उपयोग पहले कम-अंतिम उत्पादों के लिए किया जाता था, लेकिन विपणन रणनीति के कारण जुलाई 2022 के बाद उपसर्ग हटा दिया गया था।
- xix. किंगडेकोर ने इस बात से इनकार किया कि झेजियांग जियानहे या जियानहे कंपनी लिमिटेड ने एक्सएच-कोडित वस्तु का उत्पादन किया है।
- xx. किंगडेकोर का दावा है कि केडी और एक्सएच श्रृंखला को दर्शाने वाले पूर्ण उत्पाद ब्रोशर और नमूना पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गई थीं।
- xxi. किंगडेकोर प्रतिक्रिया में विलंब को स्वीकार करता है लेकिन इसे अनुरोध पर भ्रम के कारण मानता है और दावा करता है कि उन्होंने सत्यापन चरण के दौरान पर्याप्त अनुरोध किए थे और इससे प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- xxii. इसने आगे अनुरोध किया कि संशोधित परिशिष्ट 3 क पहले की अनजाने में हुई चूक को ठीक करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और सभी परिवर्तन सटीक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुरूप थे और गुमराह करने के लिए नहीं थे।
- xxiii. किंगडेकोर ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी उसके प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार करें तथा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क मार्जिन निर्धारित करें।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अनदेखी से बचने के लिए "उपयोग के लिए तैयार" शब्द जोड़े गए थे।
- ii. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में परिवर्तन करने और व्यापक समीक्षा के अनुसार सभी मापदंडों की जांच करने का निर्णय लेते हैं, तो घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि समीक्षा के बाद शुल्क को पांच साल की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।
- iii. किंगडेकोर ने महत्वपूर्ण सूचना को दबा दिया है और उस पर शेष शुल्क लगाया जाना चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से उनका समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

56. प्राधिकारी ने पहले ही लागत प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है और पाया है कि घरेलू और निर्यातक दोनों उत्पादकों के लिए कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत कच्चे माल की लागत से थोड़ी कम बढ़ी है, जिससे पुनः मात्रा निर्धारण अनावश्यक हो गया है। इसके अलावा, कच्चे माल की लागत में वृद्धि की तुलना में आयात कीमत में कम वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि को उचित ठहराएगी, जबकि वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क में कमी की मांग करने वाले निर्यातक/आयातक द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि लागत में परिवर्तन स्थायी प्रकृति के हैं जो पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण को वास्तविक रूप से प्रभावित करेंगे। प्रकटन विवरण के उत्तर में भी, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उनके द्वारा पहचाने गए परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति के थे।
57. प्राधिकारी ने नोट किया कि 'प्रिंटेड रेडी-टू-यूज डेकोर पेपर' को छोड़कर "रेडी-टू-यूज" शब्द व्यक्तिपरक है और उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ दलों द्वारा तर्क दिया गया है, प्राधिकरण इस बात से सहमत है कि यह कुछ उदाहरणों में वर्गीकरण और कार्यान्वयन में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। चूंकि प्रिंटेड डेकोर पेपर पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि इस वाक्यांश को हटाने से मूल परिभाषा का आशय नहीं बदलता है और आयातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी कार्यान्वयन कठिनाइयों को दूर करेगा। इसलिए, प्राधिकारी स्पष्टता और आसानी सुनिश्चित करने के लिए "रेडी-टू-यूज" वाक्यांश को हटाने की सिफारिश करते हैं।
58. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि नए उत्पादक/निर्यातक जो जांच की मूल अवधि के दौरान भारत को उत्पाद निर्यात नहीं कर रहे थे तथा जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है। तथापि, वर्तमान जांच के अनुसार उक्त उत्पादक/निर्यातकों को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा करने तथा आवेदकों द्वारा आरोपित परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर मार्जिन का पुनः मात्रा निर्धारण करने के लिए शुरू की गई थी। चूंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पुनः मात्रा निर्धारण के लिए आधार मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में किसी भी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। इस नियमावली में नए शिपर्स के मामले में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के उपाय का प्रावधान है, तथा नए उत्पादक/निर्यातक संबंधित नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
59. प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि किसी भी उत्पादक के लिए पुनः मात्रा निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। किंगडेकोर को छोड़कर इन प्रतिवादियों के लिए शुल्क संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। चूंकि उनके शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है, इसलिए संशोधित प्रकटन विवरण अनावश्यक है। इसके अलावा, प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है।
60. प्राधिकारी किंगडेकोर के इस तर्क पर गौर करते हैं कि उसने सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। प्राधिकारी का मानना है कि उक्त उत्पादक ने मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में भी आवश्यक तथ्यों को छिपाया है।
61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने कहा है कि उसने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था। उक्त उत्तर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी मामले में, वर्तमान जांच परिणामों में प्राधिकारी का निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा वांछित अनुपूरक सूचना पर आधारित नहीं है।
62. जबकि किंगडेकोर ने अब 158 टोंगजियांग रोड पर सुविधा के होने को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न तो मूल जांच में और न ही वर्तमान जांच में दाखिल प्रश्नावली के उत्तर में इसे प्रकट किया गया था। निर्यातक प्रश्नावली में स्पष्ट रूप से सभी उत्पादन सुविधाओं के प्रकटन की आवश्यकता है, चाहे वे कानूनी रूप से अलग क्यों न हों। डीजी प्रणाली का आंकड़ा दर्शाता है कि क्षति जांच अवधि में उक्त परिसर से बीजक जारी किए गए थे। निर्यातक ने स्वीकार किया कि उक्त संयंत्र से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया जा रहा है। प्राधिकारी का मानना है कि इस उत्पादन स्थल का प्रकट न करना तथ्यों को दबाने जैसा है।
63. किंगडेकोर का दावा है कि शाह इंटरनेशनल सर्विसेज एक असंबंधित एजेंट है। हालांकि, किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत 1 जनवरी 2019 के करार से पता चलता है कि शाह इंटरनेशनल सर्विसेज को भारत में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें एक कमीशन संरचना थी। प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जांच में किंगडेकोर के उत्तर में इस संबद्धता का प्रकटन नहीं किया गया था, और भुगतान किए गए कमीशन को समायोजन के लिए संगत परिशिष्टों में सूचित नहीं किया गया था। इसने निर्यात कीमत निर्धारण के लिए संगत महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने जैसा है।
64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किंगडेकोर ने बिना किसी व्याख्या, स्पष्टीकरण अथवा सहायक दस्तावेज के संशोधित उत्तर प्रस्तुत किया। इस संशोधित अनुरोध ने निर्यात कीमत और बैंक शुल्क में समायोजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिन्हें पूर्व में प्रकट नहीं किया गया था। किसी भी औचित्य या सह-संबंध विश्लेषण नहीं होना सूचना की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

65. प्राधिकारी पुनः पुष्टि करते हैं कि किंगडेकोर का आचरण और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तात्पर्य से असहयोग के बराबर है।

झ. निष्कर्ष और सिफारिशें

66. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- मुद्रित सजावटी कागज को शीर्षक 4811 के अंतर्गत आयात किया जाता है तथा इसे पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है। घरेलू उद्योग मुद्रित सजावटी कागज का निर्माण नहीं करता है।
- वाक्यांश “उपयोग के लिए तैयार” की व्याख्या व्यक्तिपरक तरीके से की जा सकती है तथा यह अपवर्जन की सटीकता में कोई मूल्य नहीं जोड़ता है। उक्त शब्दों को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से हटाया जा रहा है।
- आवेदन, विचाराधीन उत्पाद की लागत तथा कीमत में परिवर्तन तथा आवेदक निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पाद मिश्रण के आरोपों के आधार पर मध्यावधि समीक्षा आरंभ करने के लिए दायर किया गया था।
- घरेलू उद्योग मुख्य रूप से संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आयातित लुगदी का उपयोग करता है। चूंकि लुगदी की लागत में वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत भी मूल जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ गई है। यह आरोप तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं देखी, क्योंकि यह कैप्टिव रूप से उत्पादित लुगदी का उपयोग करता है।
- यह आरोप कि भारत को उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि मूल जांच अवधि के दौरान आयात किए जा रहे पीसीएन अभी भी आयात किए जा रहे हैं।
- संबद्ध आयातों के भारित औसत पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग के कच्चे माल की भारित औसत लागत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक निर्यातक के पहुंच कीमत में चीन से पहुंच मूल्य कीमत में वृद्धि और घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत में वृद्धि की तुलना में भी कम वृद्धि हुई है।
- आवेदक निर्यातक द्वारा पहचानी गई परिस्थितियां सामान्य मूल्य को प्रभावित किए बिना निर्यात कीमत को एकतरफा रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। इस प्रकार, पहचानी गई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर मार्जिन के पुनः निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- न तो यह सिद्ध किया गया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति का है और न ही यह कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति या संशोधन के मामले में क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का अभाव है।
- किंगडेकोर ने महत्वपूर्ण सूचना को दबा दिया है और इसलिए इसे गैर-सहकारी निर्माता के रूप में माना जाता है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के पहलू, परिस्थितियों में बदलाव और मार्जिन के पुनः मात्रा निर्धारण की आवश्यकता पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन जन.गण. में उत्पादकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के पुनः मात्रा निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

68. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड से आयात पर लगाए गए व्यक्तिगत शुल्क को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 सितंबर 2021 और अधिसूचना संख्या 77/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 दिसंबर 2021 के माध्यम से वापस लेने की सिफारिश करते हैं। अन्य उत्पादकों के संबंध में, पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा।

69. शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 दिसंबर 2021 के जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेंगे। तदनुसार, विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-डॉपिंग कर्तव्यों, चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात की गई या तत्काल मध्यावधि समीक्षा जांच में प्राधिकरण की सिफारिश को शामिल करते हुए, कर्तव्य के प्रतिबंध की शेष अवधि के लिए विशेष होगा, जैसा कि नीचे दिए गए ड्यूटी टेबल में संकेत दिया गया है।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	विवरण *	मूलता देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	शेडोंग बाक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं.,	110	एमटी	यूएसडा.

					लिमिटेड			
2	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	ज़िबो ओयू- एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड	110	एमटी	यूएसडा.
3	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	हांगजो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	297	एमटी	यूएसडा.
4	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2 और 3 के अलावा कोई भी उत्पादक	542	एमटी	यूएसडा.
5	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	542	एमटी	यूएसडा.

*40-130जीएसएम के रील रूप में बिना लेपित कागज, जिसमें 10 मिनट में कम से कम 12 मि.मी. की क्लेम अवशोषण क्षमता, 6-12 एन/15 मि.मी. की गीली तन्य शक्ति और 10-40 सेकंड/100 मिलीलीटर की गुर्ली छिद्रता हो, जिसमें भराव के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या रंगद्रव्य हों। यह उच्च दाब (एचपीएल) या निम्न दाब (एलपीएल) सजावटी लेमिनेट के लिए आधार कागज है, जिसे डेकोर पेपर, सजावटी आधार कागज, उच्च दाब या निम्न दाब लेमिनेट के लिए सजावटी कागज, कोटिंग आधार कागज और प्रिंट आधार कागज के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर जैसे सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), बेरियर पेपर, शटरिंग आधार, ओवरले पेपर और मुद्रण आधार पेपर(रंगीन/सफेद) शामिल है लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है। वैक्सीन, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; सजावट उद्योग में उपयोग के लिए बेस पेपर और अवरोधक पेपर के रूप में इनका आयात किया जा सकता है और ये विभिन्न आकारों जैसे 95 से.मी., 96 सेमी, 102 से.मी., 123 से.मी., 123.5 से.मी., 124 से.मी., 124.5 से.मी., 125 से.मी., 131 से.मी., 132 से.मी., 183 से.मी., 184 से.मी. और 185 से.मी. में आ सकते हैं।

ज. आगे की प्रक्रिया

70. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New delhi, the 25th March, 2025

Case No – MTR 03/2023

Subject: Mid-Term Review of anti-dumping duty on imports of Decor Paper originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. -7/15/2023-DGTR .—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”);

1. The anti-dumping investigation into imports of Decor Paper (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) was initiated vide Notification dated 30th September 2020 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) vide final findings F. No. 6/38/2020-DGTR dated 28th September 2021 recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country. The Ministry of Finance vide Notification No. 77/2021 – Customs (ADD) dated 27th December 2021 imposed the anti-dumping duty on imports of the subject goods from subject country.
2. Post issuance of the final findings notification No. 6/38/2020-DGTR, an exporter of the subject goods from China PR, namely, Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd. and an Indian importer, namely, Fakirsons Papchem Private Limited, preferred a Special Civil Application No. 16555 of 2021 on 18th October 2021 before the Hon'ble High Court of Gujarat, against the Department of Commerce (Respondent No. 1), Department of Revenue (Respondent No. 2) and the Designated Authority (Respondent No. 3), challenging the final findings. The writ applicants contended that the exporter was treated non-cooperative, even though it had submitted the required information and data as called for by the Authority. The Hon'ble High Court directed the Authority to take into account the submissions made by the said exporter and issue a recommendation in this regard. Based on the direction given by the Hon'ble High Court, the Authority considered the submissions made by the exporter and issued Final Findings dated 10th April 2022, which were given effect by the Ministry of Finance vide Notification No. 15/2022-Customs (ADD) dated 24th May 2022.

3. The Designated Authority received an application, one on behalf of Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd and Fakirsons Papchem Private Limited (hereinafter also referred to as the “applicant exporter/importer”) requesting re-quantification of margins.
4. The Designated Authority received another application from Indian Laminates Manufacturers’ Association (hereinafter also referred to as the “applicant association”) on behalf of its members Century Plyboards (India) Limited, Merino Industries Limited, JKS Decor Paper LLP and Thansau Decors Private Limited requesting for clarification of the scope of the product under consideration.
5. And whereas, in view of the duly substantiated applications filed by the applicant exporter/importer and applicant association, the Authority issued a public notice vide Notification No. 7/15/2023-DGTR dated 28th March 2023, published in the Gazette of India, initiating comprehensive mid-term review of anti-dumping duty imposed on imports of Decor Paper originating in or exported from China PR in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present mid-term review application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 28th March 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the mid-term review of anti-dumping duty on import of subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant exporter/importer and applicant association and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the applications to the domestic industry, known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority sent exporter’s questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Changle Keyuan Paper Company Limited
 - ii. Hangzhou Huawon New Material Technology Company Limited
 - iii. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.
 - iv. Qifeng New Material Ltd.
 - v. Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.
 - vi. Xianhe Co., Ltd.
 - vii. Zhejiang Xianhe New Materials Sales Co., Ltd.
 - viii. Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.
 - f. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from China PR to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

- g. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
- i. Changle Keyuan Paper Company Limited
 - ii. Hangzhou Huawon New Material Technology Company Limited
 - iii. Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.
 - iv. Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.
 - v. Winbon Technocell New Materials., Co., Ltd.
 - vi. Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.
- h. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Aica Laminates India Private Limited
 - ii. Century Plyboards Limited
 - iii. Color Experts
 - iv. Deco Mica Limited
 - v. Fakirsons Papchem Private Limited
 - vi. Fancy Roto Prints
 - vii. Greenlam Industries Limited
 - viii. JKS Decor Paper LLP
 - ix. Maruti Decor
 - x. Maruti Paper Chern
 - xi. Match Graphics Private Limited
 - xii. Matchwell
 - xiii. Mbee Paper Prints Private Limited
 - xiv. Merino Industries Limited
 - xv. Microteck Printage Private Limited
 - xvi. Pixel Printers
 - xvii. Printech Industries
 - xviii. Sanwaliya Impex LLP
 - xix. Saraf Sales Corporation
 - xx. Saya Paper Print Private Limited
 - xxi. Shinddecor
 - xxii. Shivam Paper Print
 - xxiii. Silver Paper Print
 - xxiv. Slick Mica Private Limited
 - xxv. Stylam Industries Limited
 - xxvi. Surface Dekor Private Limited
 - xxvii. Tanish Industries Private Limited
 - xxviii. Unique Decor (India) Private Limited
 - xxix. Vinayak Decor Vision Printers
- i. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
- a. Thansau Decors Private Limited
 - b. Fakirsons Papchem Private Limited
 - c. Century Plyboards Limited
 - d. Sidmark Sales Synergy LLP

e. Merino Industries Limited

- j. Request was made to the Directorate General of Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG system for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- k. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- l. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held in hybrid mode on 19th November 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- m. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- n. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- o. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 12 March 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- p. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- q. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- r. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- s. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration as defined in the original investigation and the initiation notification for the present investigation is as follow:

"The product under consideration is "uncoated paper in reel form of 40-130GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler" (herein also referred to as "Decor paper" or "subject goods"). It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.

The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.

The product under consideration is classified under the Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff customs classification 48059100. The Authority in the original finding has also considered the product under consideration which is being imported under tariff customs classification 48022090. Both the customs classifications have been considered for the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."

C.1. Views of other interested parties

8. The submissions of the other interested parties with regard to product under consideration and like article are as follows:
- i. As opposed to the submissions of the domestic industry, there is no need to alter the parameters used in the PCN methodology in the original investigation as the same covers all types of decor paper.
 - ii. Since the intention was to exclude printed decor paper from the product scope in the absence of production by the domestic industry, whether such paper is ready to use or not is immaterial.
 - iii. Since all papers, included printed paper have to undergo certain impregnation process to be used on laminations, the use of the term "ready-to-use" creates a technical qualification, causing issues at the time of clearance of the product.
 - iv. Due to use of the expression "ready-to-use", anti-dumping duty has been extended to printed paper imported under Customs heading 4811. The heading 4811 does not distinguish between printed paper whether or not ready to use, therefore, such qualification should not have been added.
 - v. In a recent order, Commissioner Appeal, Customs – Kolkata held that once decor paper is printed, it is ready to use, and thus, imports thereof is not subject to anti-dumping duty. However, it did not give a ruling on this aspect, leaving it open for interpretation.
 - vi. Since there is a provision for a separate investigation in case of circumvention, the fear of circumvention should not lead to expansion of product scope by using the phrase "ready-to-use".

C.2. Views of the domestic industry

9. The submissions of the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:
 - i. The product for which exclusion has been requested is printed ready-to-use paper, which is already excluded from the scope of the product under consideration. The petition filed by the other interested parties only requires a clarification regarding the excluded product.
 - ii. There is no need for change in the definition of the product under consideration as any change is likely to lead to circumvention of the anti-dumping duty in force.
 - iii. Contrary to the submissions of the other interested parties, the product scope has to be defined in a manner to preclude the possibility of circumvention as held by the CESTAT in Huawei Technologies Co. Ltd. V. Designated Authority.
 - iv. Printed ready-to-use paper falls under Customs heading 4811, on which the Authority did not recommend anti-dumping duty, and which does not attract any anti-dumping duty.
 - v. As opposed to the submissions of the other interested parties, the term “ready-to-use” is not hampering imports of printed decor paper, since the product itself falls under a different Customs heading.
 - vi. Substantial quantity of printed ready-to-use decor paper is being imported under HS Code 4811, implying that other parties are able to clear the same, without any challenge. The issue faced by the applicant importers is only due to misdeclaration of imports.
 - vii. As opposed to the submissions made by the other interested parties, the word “ready to use” does not lead to inclusion of HS Code 4811, as the anti-dumping duty is applicable on the product scope, as notified, when imported under the Customs classification, as notified.
 - viii. Since the issue raised by the other interested parties is concerning implementation of the duty order, the DGTR is not the correct Authority to clarify the same. The importers should approach the relevant Customs authority to redress the issues raised by them.
 - ix. The issue has been well-addressed by the customs authorities, as it has already been held by Commissioner Appeals that printed ready-to-use paper imported under HS Code 4811 is excluded from the scope of the product under consideration.
 - x. The members of the applicant association were also interested parties in the original investigation and the Authority provided ample opportunity to all the parties to provide comments on the product scope. However, no such submissions were made by the importers.
 - xi. The submissions made by the other interested parties with regard to PCN is contrary in nature. The exporter itself has submitted that the product mix has changed, it has moved up in the value chain and the consumer preference has changed. This necessitates change in PCNs.
 - xii. Contrary to the submissions made by the other interested parties, there is no bar on defining the product under consideration or exclusions from the product under consideration in a way not defined in the HS Codes.

C.3 Examination by the Authority

10. The Authority notes that the domestic industry is a producer of subject goods which are known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper. During the original anti-dumping investigation, the domestic industry had

submitted that it does not produce printed ready-to-use decor papers and thus, such papers were excluded from the scope of the product under consideration.

11. The Authority further notes, that the anti-dumping duty has been imposed on imports of product under consideration when imported under HS codes 48022090 and 48059100 only.
12. The applicant association and its members have requested clarification on scope of the product under consideration. The importers have stated that the domestic industry does not manufacture printed decor paper and the same should be excluded from the scope of the product under consideration. The Authority notes that printed ready-to-use decor paper is already excluded from the scope of the product under consideration. The request to change the description of the product scope and the request to remove the words “ready-to-use” from the product description has been examined in detail below.
13. The Authority notes that the anti-dumping duty imposed on imports of subject goods from the subject country has been imposed on HS Codes 4802 20 90 and 4805 91 00 only. Printed decor paper does not fall in the said HS Codes but falls under the heading 4811. The Authority has not recommended imposition of anti-dumping duty on imports under the said heading. The Notification issued by the Ministry of Finance also does not impose anti-dumping duty on such heading.
14. The Authority notes that the precise product description is important to ensure that while the objective of trade remedial action is effectively met, it has no unintended consequences for other products which are not subject to anti-dumping duty. The Authority notes that the scope of the product under consideration should not be ambiguous so as to leave the definition open to interpretation and cause undue burden to the importers of the products which are not subject to the anti-dumping duty. It is undisputed that the domestic industry is not aggrieved by imports of printed decor paper. There are no contentions that it is a like or interchangeable product to the product under consideration. The domestic industry has not offered any justification as to why “ready to use” phrase is necessary. The phrase can be interpreted in a subjective manner and does not add any value to the preciseness of the exclusion. As determination of scope of product under consideration is an important foundation on which the anti-dumping proceedings are initiated and anti-dumping duty is levied, the Authority notes that it is necessary for the Authority to provide a clarification on the same.
15. In the interest of equity, the Authority, therefore, finds it appropriate to clarify that imports of printed decor paper under heading 4811 are expressly excluded from the scope for product under consideration for levy of anti-dumping duty. Hence, the Authority drops the word “ready-to-use” from the scope of the product under consideration. The following definition shall be applicable.

"The product under consideration is "uncoated paper in reel form of 40-130GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler" (herein also referred to as "Decor paper" or "subject goods"). It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed decor paper classifiable under 4811."

16. With regard to change in PCN, the Authority has not received comments within the given timelines from any interested party, including the domestic industry for the present investigation. Hence, the

PCN methodology adopted in the original investigation has been considered for the present mid-term review.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of other interested parties

17. No submissions have been made by the applicants or other interested parties regarding the scope of the domestic industry and standing.

D.2 Views of the domestic industry

18. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:
- There are three producers of subject goods in India namely, ITC Limited, Pudumjee Paper Products and Shree Krishna Papers.
 - ITC Limited accounts for major proportion of Indian production and constitutes domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

19. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

20. The Authority concludes that ITC Limited accounts for major proportion of domestic production in India and is not related to any exporter or importer of the subject goods in India. Further, ITC Limited has not imported the subject goods in India during the period of investigation. Thus, ITC Limited constitutes the domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of the other interested parties

21. The other interested parties have not made any submissions with regard to the confidentiality claimed by the domestic industry.

E.2. Views of the domestic industry

22. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.

- i. The questionnaire response filed by other interested parties suffer from various violations of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
- ii. The exporters/producers have claimed the names of the products sold by them confidential without providing a justification. Kingdecor has even claimed its brochure confidential.
- iii. Winbon has not disclosed the product type (PCN) exported by it to India, production facilities, affiliations and shareholder information.
- iv. Huawang and Sidmark have claimed channel of distribution confidential in entirety.
- v. The producers/exporters have claimed Appendix-1 confidential in entirety.
- vi. Winbon, Huawang and Changle have failed to provide methodology used for reporting expenses claimed as adjustment for fair comparison.
- vii. Kingdecor, Changle, Shandong and Zibo have claimed all information regarding company affiliations and shareholders confidential.
- viii. Changle, Shandong and Zibo have claimed production process confidential.
- ix. Kingdecor has claimed list of raw material used confidential.
- x. Kingdecor has claimed the entire set of information in the response confidential, due to which the domestic industry is unable to understand even the nature of information submitted.

E.3. Examination by the Authority

23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

F. SCOPE OF THE PRESENT MID-TERM REVIEW**F.1. Views of the other interested parties**

26. The other interested parties have made the following submissions on the scope of the mid-term review.
- i. The initiation of comprehensive review is apt as (a) the issues highlighted for re-determination of margins are applicable to all producers, (b) the duty has been in force for a considerable period of time and (c) the situation of domestic industry has improved. The judgement in Haryana Vidut, Prasaram Nigam Limited V. Gulshan Lal is not applicable as there is an obligation on the Authority to review the need for continued imposition of duty. The right of domestic industry has not been affected as the Authority has an option to extend the revised duty for a period of 5 years.
 - ii. There has been significant change in the cost and price of basic raw material and other factors of production after imposition of anti-dumping duty. This has led to a change in product mix.
 - iii. The Authority is required to ensure that the anti-dumping duty does not exceed the margin of dumping and injury at any point of time. The requirement of changes of lasting nature applies only in cases of revocation of duty, and not for re-quantification of duty.
 - iv. There has been an increase in pulp cost by 20-30% and cost of other key inputs such as titanium, kaolin, energy and labour, leading to increase in cost of production of subject goods of about 15-30%, post imposition of duty.
 - v. Cost and price of basic raw material and other inputs have increased significantly in the global market, including for ITC. These trends are of lasting nature and likely to continue.
 - vi. There has been shift in imports towards high priced and quality product indicating shift in consumer preference, which is of a lasting nature.
 - vii. The Authority should not have initiated a full mid-term review since the applicants and the domestic industry have not requested for redetermination of margins for all producers / exporters from China.
 - viii. As per Rule 23, anti-dumping duty cannot be enhanced pursuant to an anti-dumping investigation. The Authority may accept or reject the claims of the applicants. Since none of the applicants have requested enhancement of anti-dumping duty, there is no possibility of increasing the duty in force.
 - ix. Duty in the current investigation should either be maintained or reduced but cannot be enhanced. The domestic industry has not even requested for enhancement of anti-dumping duty.
 - x. Changle did not export the subject goods to India during the original period of investigation, and should be granted individual duty based on response filed in present investigation.
 - xi. Kingdecor has filed a complete response in the present investigation and it should be granted individual margin based on the information submitted.

- xii. Winbon Technocell is a new producer and exports only high-end products to all countries including India at undumped prices.
- xiii. Due to change in product mix and cost and prices of the subject goods, there is a need for re-quantification of anti-dumping duty applicable on Hangzhou Huawang.

F.2. Views of the domestic industry

27. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions
- i. Since the scope of the present investigation is much wider than the application filed and the relief sought by the applicants, the present mid-term review should be terminated.
 - ii. Since the present review is not a sou moto review and has been initiated based on application filed by exporters and importers, the scope of the present investigation should be restricted to the relief sought. Further, there are no grounds or factors justifying sou moto review in the present investigation.
 - iii. There was no positive evidence provided by the applicants which justify initiation of a comprehensive review.
 - iv. The exporter has not established how the changes stated justify a review, especially as the dumping margin would not have changed in light of the changes identified.
 - v. As opposed to the submissions made by the interested parties, there is no provision or jurisprudence to state that anti-dumping duty should not exceed dumping margin or injury margin, at any point of time. No investigating authority barring the USA, conducts repeated review of the anti-dumping duty to ensure that the quantum does not exceed present dumping.
 - vi. The factors identified by the exporters for re-quantification of margins cannot be considered to be changes of lasting nature, warranting re-quantification of duty.
 - vii. Fluctuation in cost of raw material is a routine business scenario since the prices of pulp tend to fluctuate globally. In fact, pulp prices have declined post the period of investigation. Such change cannot be considered that of lasting nature.
 - viii. There is no evidence that the consumer preference has changed in India towards higher priced product warranting re-quantification of anti-dumping duty.
 - ix. The change in product mix and increase in exports of high-priced product is a consequence of fixed form of duty which makes lower priced products more unviable. This cannot be considered a ground for re-quantification of duty.
 - x. Increase in cost and price of subject goods cannot be a ground for re-quantification of duties as such increase implies increase in non-injurious price, landed price, constructed normal value and export price and consequently has no impact on the quantum of duty.
 - xi. Conducting a mid-term review for change in product mix and change in cost and price of subject goods would lead to a never-ending cycle of reviews.
 - xii. As opposed to the submissions by the other interested parties, Rule 23 allows the Authority to re-quantify the duties, which includes enhancement of duties. The Authority has enhanced anti-dumping duty in previous investigations, even when the application was filed for removal of duties.

- xiii. There is a possibility of manipulation of prices by the applicant exporter in order to attain a lower dumping margin. The volume of exports by such exporter is quite low as compared to demand in India and the sales have been made to sole selling agent in India. There is a possibility that the exporter and importer have colluded to price product at higher prices for a short duration.
- xiv. The applicant exporter has sold small volumes to other importers at prices much below the prices to the applicant importer. Due to this there is doubt on the bona fide transactions between the applicant producer and applicant importer.
- xv. In case, the Authority continues a comprehensive review, the duties should be recommended to continue for a further period of 5 years. This is in line with the Manual of Operating Practices.
- xvi. There is a need to check the volume of imports from Changle as compared to volume of imports from other producers. If such volume is not significant, it leaves scope for manipulation of prices for obtaining lower margin.
- xvii. The requirements of a new-shipper review should not be by-passed in the present investigation. The exports made by producers which did not export in original period of investigation, should be in commercial quantities for granting individual margins.
- xviii. The product profile of the exporter and the volume of exports of different product types must be sufficient to grant individual anti-dumping duty.
- xix. The related party of Kingdecor which is a producer of product under consideration has not participated in the present investigation.
- xx. Kingdecor has filed misleading declaration as its related party has exported the subject goods to India during the period of investigation and post period of investigation. Such goods have been cleared under the anti-dumping duty applicable for Kingdecor, even though such goods were not manufactured by it.
- xxi. While Kingdecor claimed that the related party Xianhe, is not a manufacturer of subject goods, it is evident from the decision of the Commissioner of Customs that the Xianhe is a producer of the product under consideration.
- xxii. Individual duties given to Kingdecor should be withdrawn as it suppressed essential information in the original anti-dumping investigation and provided misleading information.
- xxiii. Change in cost and prices of the product under consideration does not lead to change in dumping margin as the same impacts export price, constructed normal value, landed price and non-injurious price.

F.3. Examination by the Authority

- 28. The Authority notes that the scope of the mid-term review is different from original investigations and sunset reviews. In a mid-term review, the Authority is required to investigate and determine the need for the continued imposition of an anti-dumping duty in force, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for such a review, after elapse of reasonable period of time since the imposition of the definitive anti-dumping duty. Further, the Designated Authority is required to determine whether injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty in force is

removed or varied. If the Authority comes to a conclusion that the anti-dumping in force is no longer warranted, the Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal.

29. The Authority has previously noted as follows with regard to the scope of a mid-term review in 4,4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA), originating in or exported from China PR.

“The language of the rules concerning sunset review and midterm review has been deliberately kept different so as to emphasize more on the cautiousness of establishing the need for withdrawal. The emphasis on word “not” likely in Rule 23 (1A) of AD Rules, signifies a higher and stringent obligation while examining premature withdrawal of antidumping duty.”

30. The Authority notes that the present review has been initiated based on allegation of change in circumstances by the applicant exporter/importer. The applicant has alleged that there has been a change in the product mix being exported to India and the cost and price of the subject goods has changed which justify re-quantification of duties. No evidence has been submitted by the applicant exporter that the parameters identified are unique and applicable to the said exporter only. The Authority notes that since the parameters identified are applicable to all exporters in the subject country and not limited to only the applicant exporter, the Authority had initiated a comprehensive review.
31. The Authority notes that at the time of initiation, the applicant exporter/importer provided evidence with regard to an increase in cost of basic raw material, that is, pulp as well as increase in price of other inputs including titanium dioxide as well as kaolin. The applicant exporter/importer submitted that due to increase in the cost of raw material and inputs, the cost of production of the product under consideration increased. Further, it is submitted that the domestic industry has its own pulp and thus, the cost of production of the applicant did not increase necessitating re-quantification of anti-dumping duty. Based on the prima facie evidence, the Authority initiated the mid-term review. Further, based on the nature of contention, the Authority considered it appropriate to initiate a comprehensive review.
32. The Authority has considered all submissions made in the present mid-term review. The Authority notes that the domestic industry has submitted its financial & cost data which demonstrates as shown in the table below, that the cost of raw material has increased for the domestic industry as well. Thus, the Authority notes that the submission made at the time of initiation that the increase in cost of raw material is not applicable to the domestic industry, is factually incorrect.

SN	Raw Material	Price		Difference	
		Original investigation	Current investigation		
		₹/MT	₹/MT	₹/MT	%
1	Pulp-Import	***	***	***	***
2	Pulp-Captive	***	***	***	***
3	Chemicals	***	***	***	***
4	Broke	***	***	(***)	(***)
5	Total RM cost			***	22%

33. The Authority further notes that the total cost of raw material for the domestic industry has also increased in the present period of investigation as compared to the original period of investigation. Hence, the Authority concludes that the domestic industry has also been impacted due to increase in raw material costs.
34. With regard to the submissions that the export price to India has increased, the Authority notes that the weighted average landed price has increased less than the increase in weighted average cost of raw material of the domestic industry. While the weighted average cost of raw material has increased by 23%, the weighted average landed price of imports from China increased by 22%.

PCN code	Volume as per DG System	Cost of Raw Material			
		Original investigation	Present investigation	Difference in	Difference in
		₹/MT	₹/MT	₹/MT	%
1C1	53	***	***	***	***
1C2	52	***	***	***	***
1U2	0	***	***	***	***
2C1	699	***	***	***	***
2C2	12,341	***	***	***	***
2U1	14,328	***	***	***	***
2U2	10,128	***	***	***	***
3C1	4,050	***	***	***	***
3C2	400	***	***	***	***
3U1	11,462	***	***	***	***
3U2	2,799	***	***	***	***
Difference*				***	23%

*Weighted average

Particulars	UoM	Value
Weighted average landed price in original POI	₹/MT	128,817
Weighted average landed price in current POI	₹/MT	158,055
Increase in landed price for the applicant exporter	₹/MT	***
Increase in weighted average landed price of imports	₹/MT	29,238
Weighted Average Increase in Landed price	%	22.69%

35. Further, the Authority notes that the landed price of the applicant exporter has increased even less than the increase in landed price from China PR.

PCN code	Hangzhou Huawang New Material Technology Co.,Ltd				
	Original Investigation		Current Investigation		Difference in Present and Original
	Volume	Landed Price	Volume	Landed Price	
	MT	₹/MT	MT	₹/MT	₹/MT
1C1	***	***	***	***	***
1C2	***	***	***	***	***

1U2	***	***	***	***	***
2C1	***	***	***	***	***
2C2	***	***	***	***	***
2U1	***	***	***	***	***
2U2	***	***	***	***	***
3C1	***	***	***	***	***
3C2	***	***	***	***	***
3U1	***	***	***	***	***
3U2	***	***	***	***	***
Total (weighted average)	***	***	***	***	***

36. The Authority further notes that while the applicant exporter had relied upon the fact that the domestic industry has captive pulp consumption due to which it did not face increase in cost of production. Post verification of the information, it is noted that the domestic industry has used only 10-20% of captively produced pulp and has imported 80-90% of pulp for production of the subject goods during the period of investigation. Thus, the domestic industry has also been impacted by the increase in price of pulp.
37. Thus, the Authority concludes that the ground that the export price has increased in India does not establish a need for re-determination of dumping margin and injury margin. It is seen that even cost of production has increased because of increase in the raw material costs. It is also noted that the applicants or other interested parties have not identified any factor that has unilaterally changed only the export price, without impacting the normal value. It is therefore not established that the circumstances have materially changed compared to the POI of the original investigations. Further, it is not established that change in the circumstances are of lasting nature. Hence, there is no requirement to re-determine the margins for the applicant exporter.
38. The Authority further notes that mere change in cost and price of the product under consideration cannot be considered as change in circumstances warranting modification of measures. Cost and price may change depending upon market situation. What is material is whether the changes are lasting in nature, therefore warranting modification of measures. The Authority further notes that as per data on record, the pulp prices increased in the period of investigation but declined thereafter in the post POI. Thus, the nature of the product is such that there is fluctuation in raw material prices.
39. The Authority, based on the analysis hereinabove, found that the ground for initiation of mid-term review that the cost of production and export price has increased without commensurate increase in cost of the domestic industry, is not established.
40. The applicant exporter/importer also alleged that the product mix has changed which warrants re-determination of margins. The Authority notes that in the original anti-dumping investigation, the Authority formed PCNs. The Authority has analysed the PCNs sold in the original investigation and compared the same to the present investigation. It is noted that the PCNs imported in the original investigation are also being imported in the present investigation. Further, the PCN which were significant in quantity continue to remain in significant quantity in the present period also. Thus, the pattern of export has not undergone material change which can justify re-determination of dumping margin and injury margin, and modification of the measures. The investigation has shown that the

ground made in the application that the product mix has changed, identified at the time of initiation, is not established.

PCN code	Import Volumes	
	As per Original Investigation	As per Current Investigation
	MT	MT
1C1	-	53
1C2	326	52
1U2	-	-
2C1	1,107	699
2C2	10,091	12,341
2U1	4,278	14,328
2U2	2,378	10,128
3C1	2,634	4,050
3C2	372	400
3U1	2,902	11,462
3U2	401	2,799

41. The Authority holds that the applicant is required to establish a change in circumstances to such an extent that the basis on which the duty was imposed has altered so materially that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the anti-dumping duty in force is removed or varied. In light of submissions made by all the interested parties in the present investigation, and considering the facts established during the course of the present investigation on the basis of information and positive evidence on record, the Authority concludes that the grounds identified as change in circumstances do not exist. The investigation has shown that the interested parties have not established that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the existing anti-dumping duty is removed or varied. It is not established that the ADD is no longer warranted.
42. The Authority further notes that the other interested parties have submitted that Kingdecor consistently supplied goods manufactured by Xianhe Co. Ltd., a related entity, while falsely representing Xianhe as merely a trader. Kingdecor declared these goods as its produce to evade the anti-dumping duty imposed on the subject goods. It has been observed that Kingdecor has also exported goods produced in a factory no 158, Tongjiang Road, Shenjia Development Zone, Quzhou City, Zhejiang 324022, China. However, the same was never reported as a manufacturing/production unit by Kingdecor both in the original investigation as well as the MTR investigation.
43. Upon inquiry regarding these two plants, the exporter submitted that its first production line, identified as Line No. 13, was installed in 2006 at No. 158 Tongjiang Road, Shenjia Economic Development Zone, Quzhou City, Zhejiang Province. In October 2011, the company expanded its operations to the current official/registered address at No. 20, South Tianhu Road, Quzhou City, Zhejiang Province. Kingdecor also stated that its business license includes only one official/registered address—No. 20, South Tianhu Road. Based on this, Kingdecor claimed that it reported only the official address while filing the EQR. Further the exporter admitted that during the POI it has exported PUC produced from both the plants.

44. However, it is evident from the Exporter Questionnaire Response requirements that such disclosure is insufficient and amounts to material suppression of facts. Points 3 and 4 of the General Section of the EQR are reproduced below for reference:

“3. List the complete address of your main corporate office and your office in India, if any. Provide their telephone, fax numbers, and e-mail address. State the name, address, telephone, fax numbers, and e-mail address of the principal contact person (or representative/legal representative in India or elsewhere for the purpose of anti-dumping proceedings).

4. List the factories involved in the production of the product under investigation, with complete address, telephone and fax numbers, and e-mail address.”

45. These requirements clearly mandate that exporters must disclose not only the corporate office address but also the complete details of all factories involved in the production of the product under consideration. Information with regard to all manufacturing facilities is very critical information, as the Authority is required to know complete information on production and sale of goods by the company under investigation. Additionally, Appendix-7 of the EQR requires expenses and cost information to be reported separately for each plant/unit producing the PUC. This issue raises serious doubt about the authenticity of the information submitted by Kingdecor.

46. The Authority also notes that Kingdecor failed to disclose its business relationship with Shah International Services, an Indian entity involved in marketing its products. Upon questioned, Kingdecor admitted to the business relationship, submitting the following explanation:

As explained above, Kingdecor has only one unrelated Indenting agent namely Shah International Services in Indian market. As per the requirement of Indian buyers, Shah places orders to Kingdecor and after supply of the goods by Kingdecor to the Indian buyers, it gets a commission @2% on the sale value of the goods.

The commission along with rebate (if any) paid during the POI of the original investigation as well as in the present MTR investigation by the Company has been duly reported in Appendix 7 of the EQR submitted by Kingdecor under the head “Direct Selling Expenses”, titled as “Commission on Sales” for Company as a whole, PUC as well as Non-PUC as and where applicable, since there is no such direction of filing the same in any other appendices including Appendix-3A.

47. Further, as per the copy of the agreement provided by Kingdecor, it has entered into a written agreement (dated 1st January, 2019) with Shah International Services appointing the latter as commercial representative in India. The agreement is effective from 1st January 2019 and negotiated for an indefinite period. However, Kingdecor failed to report this vital business relationship and the adjustment of commission paid to determine the ex-factory export price, constituting suppression of material information.
48. On 11th October 2024, the Authority issued two supplementary questionnaires to the concerned exporters, stipulating a deadline of 18th October 2024 for submission of responses. Kingdecor submitted a request seeking an extension of seven (7) days, i.e., until 25th October 2024. However, no response has been received from Kingdecor to date with respect to the said questionnaires. Supplementary Questionnaires contain significant information for the determination of dumping margin and injury margin.

49. Kingdecor also failed to get its information verified, to substantiate the accuracy of the information furnished. The Authority, vide email dated 18th October 2024, directed Kingdecor to furnish the requisite verification documents by 25th October 2024. The said communication explicitly instructed Kingdecor to provide an explanation elucidating the correlation between the commercial invoice and other relevant supporting documents. It has been observed that Kingdecor has failed to adhere to these instructions, as no explanation has been provided to establish the correlation between the commercial invoice and the accompanying documents.
50. Furthermore, Kingdecor has submitted a document titled "Appendices-Kingdecor (Zhejiang) Co. Ltd Appendix 3A-recorrection," along with verification documents representing a revised version of Appendix 3A originally submitted with its Exporter's Questionnaire Response (EQR). However, neither the covering email nor the revised Appendix 3A contains any clarification or justification regarding the reasons for such revision. It is seen that modifications pertaining to adjustments in the export price to India have been made in the revised document, which amounts to a material change in the questionnaire response without any intimation, clarification or justification. Additionally, bank charges, which were not disclosed in the original EQR, have now been reported in the revised submission without any explanatory note or corroborating evidence to substantiate this amendment. These discrepancies cast doubt on the completeness, accuracy, and reliability of the data furnished by Kingdecor. The Authority notes that the exporter has on its own revised the questionnaire response and that too without any intimation, clarification or justification, thus rendering the original questionnaire response redundant. The absence of justifications for material revisions and the failure to comply with explicit instructions has adversely impacted the credibility of the information submitted in the context of the ongoing investigation.
51. In view of the foregoing, it is evident that Kingdecor (Zhejiang) Co. Ltd. has not cooperated fully with the present investigation. Further, the producer also suppressed material information in the original investigation, based on which the Authority granted Kingdecor individual duties. The suppression of material information in original as well as present investigation, failure to submit requisite documents, inconsistent disclosures, and non-compliance with specific instructions constitute non-cooperation under Rule 6(8) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (Anti-Dumping Rules). The Authority has changed the quantum of anti-dumping duty imposed on imports from Kingdecor and the producer shall be subjected to residual duties.
52. The Authority notes, based on the analysis above, that the matter does not warrant re-quantification of individual margins of the applicant exporter or any other producer from China, barring Kingdecor (Zhejiang) Co. Ltd.

G. POST DISCLOSURE COMMENTS

G.1. Submissions by other interested parties

53. The other interested parties have made the following submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. Due to changes in cost structures, product mix, and market conditions, a re-quantification of anti-dumping duty is warranted.
 - ii. The cost of raw materials and inputs has significantly changed and has affected the competitiveness of the exporter.

- iii. Authority's observation that there has been no material change in circumstances is improper.
- iv. The methodology used for determining injury and dumping margin needs to be reconsidered.
- v. A revised disclosure statement should be issued to incorporate the comments before issuing final findings.
- vi. A clearer definition of the Product Under Consideration (PUC) be given and the words "excluding printed ready-to-use decor paper" be dropped.
- vii. The ambiguity in product classification has resulted in confusion and administrative difficulties at the time of import.
- viii. The domestic industry's concerns about circumvention are unfounded, as circumvention issues can be addressed through a separate investigation under Rule 25.
- ix. Winbon is a new producer/exporter that was not part of the original investigation and should be assigned a separate anti-dumping duty based on its own data.
- x. Kingdecor's misrepresentations have distorted the injury analysis and affected the fairness of the investigation.
- xi. The dumping margin calculations should consider high-value product sales separately.
- xii. Certain submissions by domestic industry and other exporters have been overly redacted.
- xiii. Kingdecor contests the Authority's conclusion that it was non-cooperative.
- xiv. It submitted all relevant information timely and explained its responses when prompted.
- xv. Kingdecor reiterated that No. 158 is not an independent unit, but a workshop under the same company and that all accounting, invoicing, and registration is conducted centrally from No. 20 Tianhu South Road.
- xvi. Kingdecor contends that disclosure of No. 158 was not mandatory as it was not a separate legal entity.
- xvii. Shah International Services, is a non-related indent agent operating in India and all commissions paid were disclosed under direct selling expenses in Appendix-7.
- xviii. Kingdecor clarified that both KD and XH series are produced by it and XH series was earlier used for low-end products, but prefix was removed post-July 2022 due to marketing strategy.
- xix. Kingdecor denied that Zhejiang Xianhe or Xianhe Co. Ltd. produced the XH-coded goods.
- xx. Kingdecor asserts that full product brochures and sample booklets showing KD and XH series were submitted.
- xxi. Kingdecor accepts delay in response but attributes it to confusion over the request and asserts that they made substantial submissions during the verification stage and that this should not lead to complete rejection of the response.
- xxii. It further submitted that the revised Appendix 3A was submitted to correct earlier inadvertent omissions and all changes were in line with accurate reporting requirements and not meant to mislead.
- xxiii. Kingdecor has requested that the Authority accept its questionnaire response and determine an individual anti-dumping duty margin based on verified data.

G.2. Submissions by domestic industry

54. The domestic industry has made the following submissions post-issuance of the disclosure statement:
- i. The words "ready-to-use" were added to avoid circumvention of the anti-dumping duty imposed on the product under consideration.
 - ii. In case, the Authority decides to change the quantum of anti-dumping duty and examine all parameters as per a comprehensive review, then the domestic industry requests that the duties should be continued for a further period of five years post the review.
 - iii. Kingdecor has suppressed material information and should be subjected to residual duties.

G.3. Examination by the Authority

55. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
56. The Authority has already analyzed cost trends and found that raw material costs have increased for both domestic and exporting producers. The weighted average landed price of imports has increased a little less than raw material costs, making re-quantification unnecessary. Further, an increase in the import price lower than the increase in raw materials costs would at best justify increase in the quantum of anti-dumping duty, whereas the present application is filed by an exporter/importer seeking reduction of anti-dumping duty. It is also noted that no concrete evidence has been submitted to demonstrate that the changes in costs are of a lasting nature that would materially impact the determination of anti-dumping duties. In response to disclosure statement also, there is no reference to any evidence which has been provided to incontrovertibly prove that there exist change in circumstances which are of lasting nature.
57. The Authority noted that the wording “ready to use” in “excluding printed *ready-to-use* decor paper” is subjective and militates against the preciseness which is crucial for defining the scope of product. As argued by some parties, the Authority agrees that it can create uncertainty in classification and implementation in some instances. As printed decor paper is already outside the scope of the product under consideration, the Authority considers that removing this phrase does not change the intent of the original definition and would remove any implementation difficulties that might be experienced by the importers. The Authority, therefore, recommends the deletion of the phrase “*ready-to-use*” to ensure clarity and ease in understanding.
58. The Authority acknowledges that there are new producers / exporters which were not exporting the product to India during the original period of investigation and have participated in the present investigation. However, individual margins cannot be granted to the said producer / exporters pursuant to the present investigation. The present investigation was initiated in order to review the scope of the product under consideration and re-quantification of margins based on the change in circumstances alleged by the applicants. Since the grounds for re-quantification with regard to change in circumstances do not exist, the Authority has not determined the dumping margin and injury margin for any producer in the present investigation. The rules provide remedy to seeking individual dumping margin in case of new shippers, and the new producers / exporters may approach the Authority under the relevant Rules.
59. The Authority confirms that no re-quantification is required for any producer. The duty structure remains unchanged for these respondents except Kingdecor. Since no modifications to their duty are being made, a revised disclosure statement is unnecessary. Further, the comments received by all the interested parties post issuance of the disclosure statement have been incorporated in the present final findings.
60. The Authority notes Kingdecor’s contention that it has submitted all required information. The Authority holds that the said producer has suppressed essential facts in the original as well as the present investigation.

61. The Authority notes that the exporter has stated that it had filed a response to the supplementary questionnaire. The said response was not received by the Authority. In any case, the Authority's conclusion in the present findings is not based on supplementary information desired by the Authority.
62. While Kingdecor has now acknowledged the existence of the facility at No. 158 Tongjiang Road, the same was neither disclosed in the original investigation nor in the questionnaire response filed in the present investigation. The Exporter Questionnaire clearly requires disclosure of all production facilities, regardless of legal separation. The DG System data demonstrates that invoices were issued from the said premises in the injury investigation period. The exporter admitted that subject goods are being produced and exported from the said plant. The Authority holds that failure to disclose this production site constitutes material suppression of fact.
63. Kingdecor's claim that Shah International Services is an unrelated agent is noted. However, the agreement dated 1st January 2019, submitted by Kingdecor itself shows that Shah International Services was appointed as a commercial representative in India with a commission structure. The Authority notes that this agreement was not disclosed in Kingdecor's response in the original or present investigation, and the commission paid was not reported in the relevant appendices for adjustments. This constitutes suppression of material information relevant to export price determination.
64. The Authority notes that Kingdecor submitted a revised response without any explanation, clarification, or supporting documentation. This revised submission introduced material changes in adjustments to export price and bank charges not disclosed earlier. The absence of any justification or correlation analysis severely affects the credibility of the information.
65. The Authority reaffirms that Kingdecor's conduct and suppression of vital facts amounts to non-cooperation within the meaning of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.

H. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

66. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - i. Printed decor paper is imported under the heading 4811 and has already been excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry does not manufacture printed decor paper.
 - ii. The phrase "ready-to-use" can be interpreted in a subjective manner and does not add any value to the preciseness of the exclusion. The said words are being dropped from the definition of the product under consideration.
 - iii. The application was filed for initiation of mid-term review based on the allegations of change in cost and price of the product under consideration and the product mix being exported to India by the applicant exporter.
 - iv. The domestic industry mainly uses imported pulp for manufacturing the subject goods. Since the pulp cost has increased, the cost of production of the domestic industry has also increased in the period of investigation as compared to the period of investigation in the original

- investigation. The allegation that the domestic industry did not witness an increase in the cost of production, as it uses captively produced pulp is not supported by facts.
- v. The allegation that the product mix to India has changed is not established as the PCNs which were being imported during the original period of investigation are still being imported.
 - vi. The weighted average landed price of subject imports has increased less than the increase in weighted average cost of raw material of the domestic industry. Further, the Authority notes that the landed price of the applicant exporter has increased even less than the increase in landed price from China and the increase in cost of raw material of the domestic industry.
 - vii. The circumstances identified by the applicant exporter do not unilaterally impact the export price without impacting the normal value. Thus, there is no need for re-determination of margins based on the change in circumstances identified.
 - viii. It has neither been established that the change in circumstances is of a lasting nature nor the absence of likelihood of continuation or recurrence of the injury in case of cessation or modification of the anti-dumping duty.
 - ix. Kingdecor has suppressed material information and is therefore treated as non-cooperative producer.

67. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of product under consideration, change in circumstances and need for re-quantification of margins. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that there is no need for re-quantification of anti-dumping duty applicable to producers in China PR barring Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.

68. In view of the foregoing, the Authority recommends withdrawal of individual duty imposed on imports from Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. vide Final Findings Notification No. 6/38/2020-DGTR dated 28th September 2021 and Notification No. 77/2021 – Customs (ADD) dated 27th December 2021, as below. As regards other producers, the anti-dumping duty imposed earlier would continue.

69. The antidumping duties are in force for five years from the date of issuance of Notification No. 77/2021 – Customs (ADD) dated 27th December 2021. Accordingly, the definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR incorporating above recommendation of the Authority in the instant mid-term review investigation, shall be applicable for the remaining period of imposition of duty, as indicated in the duty table appended below.

S. no.	Tariff Item	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	110	MT	USD
2	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper	People's Republic	Any country, including	Zibo OU-MU Special	110	MT	USD

			of China	People's Republic of China	Paper Co., Ltd.			
3	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd.	297	MT	USD
4	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Any other than at S.No. 1, 2 and 3	542	MT	USD
5	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper	Any Country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	542	MT	USD

**uncoated paper in reel form of 40-130GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed decor paper classifiable under 4811.*

*The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white) **but excludes printed decor paper classifiable under 4811.** It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.*

I. FURTHER PROCEDURE

70. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

DARPAN JAIN, Designated Authority